मूल्य पर किसानों को जिला स्तर पर मरम्मत की सुविधाएं और फालतू पुर्जे उपलब्ध नहीं है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उनका मंत्रालय इस प्रकार के छोटे कार्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है और पंप सेट टिलरों हेतु ऋण तथा अनुदान राशि के नियम अभी तक निर्धारित नहीं किये गये हैं और यदि हां, तो सरकार छोटे किसानों को लाभ देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ।

रसायन और पट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कृषि उपकरणों और मशीनों की खरीद के लिए वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से ऋण सुविधाएं उपलब्ध है । वैकिंग वर्ष 1985-86 के दौरान एन० ए० बी० ए० आर० डी० ने कृषि यंत्रीकरण गतिविधियों के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है ।

Target of industrial production in Seventh Plan

2159. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what was the target of industrial growth fixed for the Sixth Five Year Plan;

(b) whether that target has been achieved;

(c) the target of industrial growth proposed for the Seventh Plan; and

(d) steps being taken to increase industrial production for attaining the above target of the Seventh Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO CHEMICALS (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) The Sixth Plan envisaged an average annual rate of growth of 8 per cent of industrial production during the five year period.

(b) The actual growth rate achieved during the Sixth Five Year Plan period was 5.7 per cent.

(c) In the Seventh Five Year Plan, a growth rate of 8 per cent has been envisaged during the Plan period.

(d) For achievement of target of 8 per cent growth in industrial production, the Seventh Plan lays emphasis on planned and progressive restructuring of industry, improving infrastructural facilities, more efficient use of capital, modernisation and upgradation of technology, increasing productivity, etc.

समानान्तर डाक सेवा

2160. **श्री भंवर लाल पंवार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि देश में अभी भी गैर-सरकारी समानांतर डाक सेवा चलाई जा रही है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस सेवा को बंद करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और यदि कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) 1983 से लेकर 1985 के दौरान अब तक इस वजह से सरकार को राजस्व को अनुमानत: कितनी वार्षिक हानि हुई है; और

(ग) क्या राजस्थान में भी समानांतर डाक सेवा चलाई जा रही है और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां । देश में चल रही अनेक ऐसी सेवाओं के बारे में रिपोर्ट मिली है । जब कभी भी ऐसे मामलों का पता चलता है तो भारतीय डाकघर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए इनकी पुलिस में रिपोर्ट की जाती है ताकि ये एजेंसियां अपनी गतिविधियां जारी न रख सकें ।